VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
R
N 22 OCT 2016
SUBMITTED IN 3 HOURS
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 843)

Name of Candidate	Shailendra Singh Indoliya		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	7441
Center	ORN	Date	22/10/16

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।.
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. **Alignment Competence**
2. **Context Competence**
3. **Content Competence**
4. **Language Competence**
5. **Introduction Competence**
6. **Structure - Presentation Competence**
7. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Discuss the need for adhering to the road map for fiscal consolidation by fixing the fiscal deficit. Has the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 served the purpose for which it was envisaged?

राजकोषीय घाटा के निर्धारण के माध्यम से राजकोषीय समेकन (कंसोलिडेशन) के लिए एक रोड मैप का पालन करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। क्या राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) अधिनियम, 2003 ने अपनी परिकल्पना के उद्देश्य की पूर्ति की है?

राजकोषीय घाटा से अभिप्राय सरकार द्वारा कुल देनदारी से है। राजकोषीय घाटा के प्रभावी संतुलन होने से राजकोषीय समेकन की गतिविधि सकारात्मक होती है।

- राजकोषीय घाटा के सम्बन्ध एक परास में (Range) होने की आवश्यकता है ना कि एक नंबर के रूप में इसका निश्चित मान होना चाहिए।

- क्रेडिट वृद्धि व राजकोषीय घाटा के मध्य में नकारात्मक सहसंबंध होता है जिसे ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटा को परिवर्तनशील होना चाहिए।

- राजकोषीय घाटा की प्रभावी निगरानी हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र विकसित होना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चाहिए राजकोषीय घाटे के प्रभावपूर्ण व संतुलित स्तर पर बने रहना अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण / संतुलन के लिए आवश्यक है।

FRBM Act, 2003 की समीक्षा :
इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ में 2009 तक राजकोषीय घाटे को 3% तथा राजस्व घाटे को (GDP का) शून्य के स्तर तक बनाये रखना था। वैश्विक मंदी व किसानों के ऋण माफी के कारण इसकी सीमा बढ़ाई गई।
वर्तमान में राजकोषीय घाटा 3.9% है जिसे 2016-17 तक 3.5% तथा 2017-18 तक 3.0% करना है।
· यद्यपि यह अधिनियम प्रभावपूर्ण नहीं रहा है। क्योंकि इसके अंतर्गत राजकोषीय परिषद (कार्यों की निगरानी हेतु) की स्थापना नहीं की गई।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- वैश्विक व घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र विकसित नहीं किया गया।
- इसी संदर्भ में 14वें वित्त आयोग ने एक स्वतंत्र वित्त राजकोषीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की है।
- FRBM Act में संशोधन कर राजकोषीय घाटे की रेंज (Range) निर्धारित करने की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Public investment in railways has a multiplier effect for the larger economy. Elaborate. What factors have held back the railways despite having a separate budget and considerable resources? In this context, enumerate the relevant recommendations of Bibek Debroy committee?

रेलवे में किए गए सार्वजनिक निवेश का, वृहद् अर्थव्यवस्था के लिए गुणक (मल्टीप्लायर) प्रभाव होता है। विस्तार पूर्वक बताईए। अलग बजट और यथेष्ट संसाधनों के बावजूद कौन से कारकों ने रेलवे को पीछे रखा है? इस संदर्भ में, बिबेक देबरॉय समिति की प्रासंगिक अनुशंसाएं बताईए?

रेलवे निवेश का अर्थव्यवस्था पर गुणक रूप से प्रभाव पड़ता है।

- उद्योगों पर प्रभाव- कोयला, लोहे का आवागमन अधिकतर रेलों द्वारा होता है। रेलवे के द्वारा प्रभावपूर्ण आवागमन से इस्पात उद्योग जैसे विनिर्माण क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- खाद्य आपूर्ति की बिना बाधा के आवागमन होना।
- इनके अतिरिक्त अन्य कच्चे माल की प्रभावी आपूर्ति।
- पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रेलवे के पिछड़ने के कारण -

- स्वतंत्रता के पश्चात रेल पटरियों की संख्या में वृद्धि न होना रेल बजट के राजनीतिकरण के कारण केवल रेलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया न कि पटरियों की लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई।
- यात्री रेलों व माल भाड़ा गाड़ियों के लिए अलग पटरियों का न होना।
- रेलवे के कुल बजट के लिए निर्धारित राशि का केवल 50-79% ही अभी तक खर्च किया गया है।
- रेल किराये निर्धारण के लिए रेलवे टैरिफ प्राधिकरण का गठन न किया जाना।
- रेलवे हेतु संसाधनों के उपयोग के संबंध में निगरानी हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र का अभाव।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

विवेक देवराय कमेटी की सिफारिशें-

- रेलवे सुरक्षा तथा टैरिफ प्राधिकरण का गठन।
- क्रमबद्ध रूप से रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत करने को खत्म करना।
- रेलवे के निजीकरण के बजाय कारपोरेट प्रणाली को शामिल करना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. "There is a myth that small firms create the most jobs in an economy. The fact is that small firms that grow big create the jobs". In context of the Indian economy what are the factors that prevent firms that start small from growing bigger. What progress has India made in this respect and what other measures are required?

"ऐसा मिथक है कि किसी अर्थव्यवस्था में छोटी फर्में सर्वाधिक रोजगार पैदा करती हैं। जबकि तथ्य यह है कि वही छोटी फर्में जो बड़ी फर्मों के रूप में विकसित होती हैं, रोजगार पैदा करती हैं"। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, छोटी फर्मों को बड़ी फर्मों के रूप में विकसित होने से रोकने वाले कारक कौन-से हैं? इस संदर्भ में भारत ने क्या प्रगति की है और कौन-से अन्य उपाय आवश्यक हैं?

भारतीय अर्थव्यवस्था सीमित प्रवेश वाले समाजवाद से बिना निकास वाले बाजारवाद की ओर विकसित हुई है जिसके कारण फर्मों की क्षमताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

बड़ी फर्मों के विकास में बाधक कारक:

प्रतिबंधात्मक श्रम विनियमों के कारण फर्में छोटे रहने हेतु बाध्य हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत 100 से अधिक श्रमिकों की छंटनी हेतु सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक है।

श्रम व औद्योगिक नियम विषय के समवर्ती सूची में होने के कारण राज्यों में अलग-

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अलग कानूनों से निवेशकों को नुकसान

- होने वाले फर्मों के निकासन हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र का अभाव
- बड़ी फर्मों के रूप में विफल होने से कई छोटी फर्मों को सरकार से वित्तपन सहायता मिलना बंद हो जाता है
- Exit (निकासी) संबंधी समस्या

भारत सरकार के प्रयास -

- सरकार कानूनों में सुधार हेतु प्रयास मौलिक संहिता के निर्माण की दिशा में कार्य
- ऋणशोधन व दिवालियापन कानून, 2015 हेतु तैयार किया गया है
- हानि में चल रही फर्मों को समाप्त करने हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र विकसित किया जा रहा है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अन्य उपाय -

भारतीय उद्योगों में कंपनियों के निर्माण को सुगम बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में निहित स्वार्थों के कारण ब्यूरो में चल रही कंपनियों को भी बंद नहीं किया जाता है। ऐसी समस्याओं का त्वरित समाधान करने की आवश्यकता है।

श्रम विनियमनों को प्रतिबंधात्मक के बजाय सरल व प्रभावी बनाने की आवश्यकता जिससे वे उद्योगों के विकास में सहायक हों।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Enumerate the reasons why problem of NPAs is more pronounced in the public sector banks as compared to the private sector. Discuss the implications of having high NPAs in an economy. Also list the measures which the government has taken in order to address them.

निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एन.पी.ए. की समस्या अधिक गंभीर होने के कारण बताएं। किसी अर्थव्यवस्था में उच्च एन.पी.ए. के निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदमों को भी सूचीबद्ध कीजिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या अधिक गंभीर है।

- सार्वजनिक बैंकों का अधिक प्रभावी विस्तार या ध्यान दिया गया है। कुल ऋण के 70% से अधिक भाग सार्वजनिक बैंकों के अंतर्गत है।
- ऋण देने हेतु सरकारी दबाव से जुड़ी गतिविधियां
- सरकारी कंपनियों हेतु ऋण देने के कारण NPA की समस्या। स्टील कंपनियों की NPA में प्रमुख भागीदारी है जिसके पीछे प्रमुख कारण चीन की अधिक स्टील उत्पादन क्षमता व वैश्विक मांग का कम होना है।

VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सावधानी बैंको द्वारा ऋण देने के पहले जांच हेतु उपयुक्त नियमों का पालन न करना
- कई बैंकों के प्रबंध निदेशकों के भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलिप्तता।

⇒ उच्च N.P.A. के निहितार्थ:

उच्च N.P.A होने से बैंको द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंकों द्वारा ऋण न देने से (क्रेडिट वृद्धि नकारात्मक होना) कंपनियों द्वारा निवेश गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

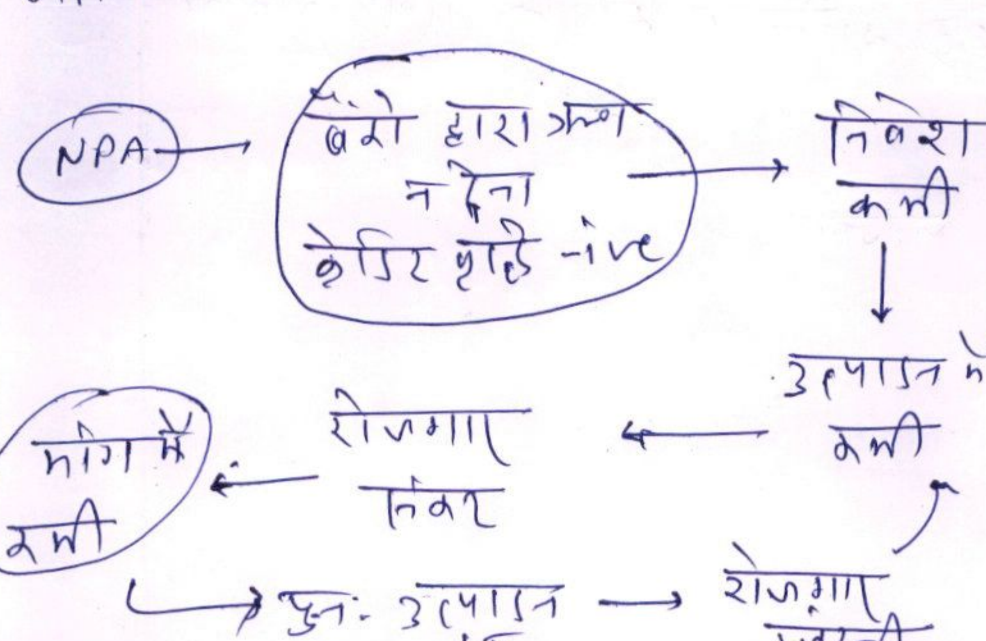

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकार द्वारा उठाये गये कदम :

- NPA की जांच प्रोत्साहित करने (शुरुआत) में करने हेतु RBI द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।
- सरफेसी अधिनियम, 2003 में प्रभावी हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया है।
- Asset Reconstruction Company को प्रभावी बनाया जाना।
- Debt Recovery Tribunal को प्रभावी बनाने हेतु शक्तियों को स्थानांतरण करके प्रयास।
- SARFAESI योजना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Mention the salient features of the Hybrid Annuity Model (HAM) proposed by the government to reinvigorate private investment in infrastructure sector. How is it an improvement over the EPC model?

अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एच.ए.एम.) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कैसे यह ई.पी.सी. मॉडल से बेहतर सुधार(इम्प्रूवमेंट) है?

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल निजी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु नया मॉडल है

इसके अंतर्गत किसी परियोजना का वित्त पोषण हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ में 40% राशि दी जाती है अन्य 60% राशि बाद में किश्तों में दी जाती है

सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति व भूमि अधिग्रहण संबंधी अनुमोदन प्रदान किया जाता है

जोखिम का संतुलित ढंग से बंटवारा किया जाता है ताकि निजी निवेशकों के निवेश पर विपरीत प्रभाव ना पड़े

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- E.P.C मॉडल (अभियांत्रिकी, आधिगम, निर्माण) में निजी कंपनी मान्यमेंट की भूमिका निभाती है जिसमें इस वित्तपोषण ~~निजी~~ सरकार द्वारा किया जाता है तथा निजी कंपनी contractor की तरह योजना पूरी कर सरकार को सौंप देती है।

- वर्तमान परिदृश्य में सरकारी वित्त कमी के कारण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल उपयुक्त है क्योंकि इसमें सरकार द्वारा प्रोजेक्ट में मात्र 40% वित्तपोषण किया जायेगा बाकी पैसा निजी कंपनी लगायेगी।

- EPC मॉडल में Toll उगाही का कार्य सरकार द्वारा किया जायेगा जबकि HAM में टोल उगाही निजी कंपनी द्वारा की जायेगी।

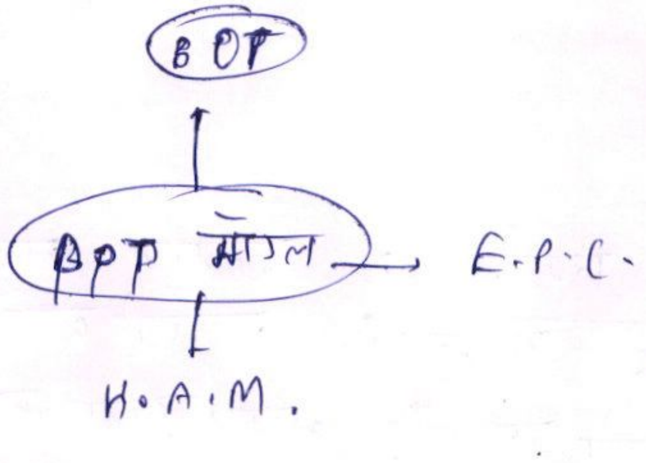

इस प्रकार H.A.M. एक उपयुक्त मॉडल है
इसमें निजी फर्मों की बैलेंस शीट पर भी
विपरीत असर नहीं पड़ेगा क्योंकि निजी कंपनियों
द्वारा पर्यावरण व भूमि अधिग्रहण स्वीकृति
न मिलने से परियोजना के लटके होने पर
<u>NPA</u> की समस्या उत्पन्न होती थी। इस
प्रकार की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Even within the multilateral format of WTO the FTA route has served India well. Comment. How can India effectively deal with the challenges posed by the new mega regional agreements such as TPP?

यहां तक कि डब्लू.टी.ओ. के बहुपक्षीय प्रारूप (multilateral format) के अंतर्गत भी भारत को एफ.टी.ए. मार्ग (FTA route) का अच्छा साथ मिला है। टिप्पणी कीजिए। भारत टी.पी.पी. जैसे नये मेगा क्षेत्रीय समझौतों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से किस प्रकार प्रभावी ढंग से निपट सकता है?

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत द्वारा बहुपक्षीय प्रारूप को प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। भारत द्वारा कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किये गये हैं।

- इस संबंध में भारत-आसियान FTA तथा दक्षिण कोरिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता महत्वपूर्ण है।
- तथापि भारत को FTA के द्वारा आयात की तुलना में निर्यात अपेक्षाकृत कम हुआ है इसके अतिरिक्त कई देशों के साथ मात्र वस्तु क्षेत्र में FTA के कारण भारत अपने सापेक्षिक व उच्च सेवा क्षेत्र का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाया है।
- भारत द्वारा FTA के अंतर्गत mode-4

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सेवाओं (श्रमिकों का अस्थायी आवागमन) का प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं किया गया है।

यद्यपि FTA के कारण भारत की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी 2001-07 के 4.8% से बढ़कर 2008-12 में 6.1% हो गई है।

=) यद्यपि WTO (विश्व व्यापार संगठन) जैसे बहुआयामी संगठन में कई असफल वार्ताओं (दोहा वार्ता) के कारण भारत स्वैच्छिक रूप से क्षेत्रीय संगठन बनाने की ओर उन्मुख हुए हैं इन संगठनों में/करारों में नये वैश्विक मुद्दे भी शामिल किये गये हैं।

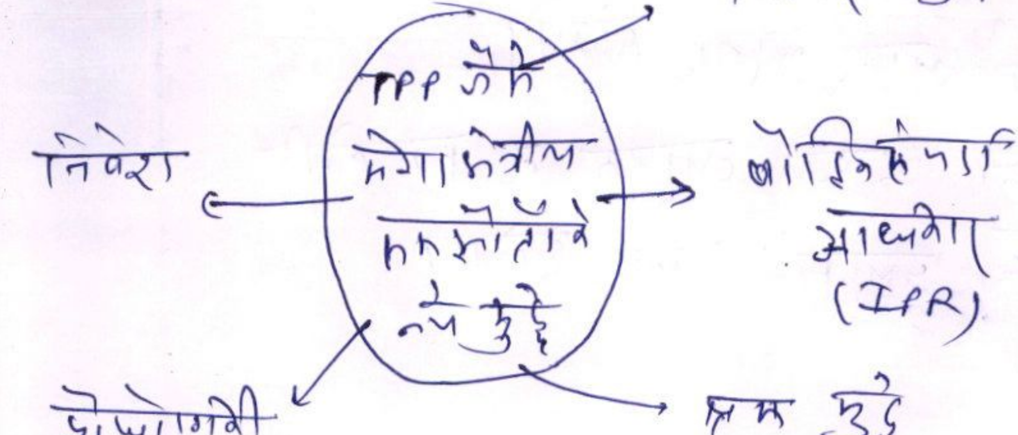

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत इन क्षेत्रीय समझौतों से अलग तटस्थ हो नहीं रह सकता क्योंकि बाद में इन समझौतों के नियमों के निर्धारण में भारत की कोई भूमिका नहीं होगी और केवल नियमों का पालन करना होगा।

- भारत को अपनी पर्यावरणीय, श्रमिक उद्योग को ध्यान में रखते हुए नये मेगा क्षेत्रीय समझौतों का हिस्सा बनने का प्रयास करना होगा जैसे- RCEP.
- भारत को FTA प्रणाली को अन्य देशों, लेकिन अमेरिकी देश जो TPP में शामिल हैं, के साथ लागू करना होगा।
- FTA को अधिक व्यापक व प्रभावी बनाने का प्रयास करना होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Cashless economy is a global trend now. What are the challenges of achieving a cashless economy in the case of India? How can these challenges be overcome?

नकदीरहित (कैशलेस) अर्थव्यवस्था अब वैश्विक प्रवृत्ति बन गई है। भारत के प्रकरण में नकदीरहित अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां क्या हैं? इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

कैशलेस अर्थव्यवस्था से आशय वित्तीय गतिविधियों में नकद के बजाय अन्य डिजिटल गतिविधियों के प्रयोग से है

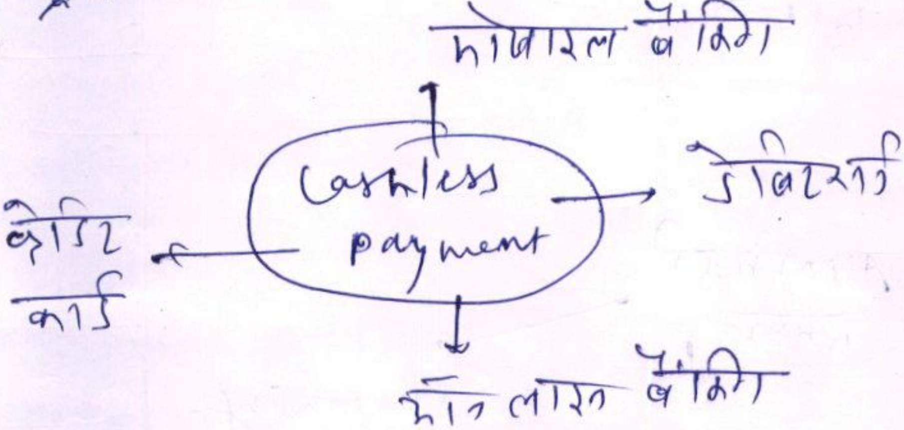

भारत के संदर्भ में कैशलेस अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद है

बैंकों के सुरक्षा मानकों के संबंध में प्रभावपूर्ण लेग न होना। हैकिंग के प्रभावी न होने के कारण हाल में 3.4 मिलियन कार्डों के

संबंध में धोखाधड़ी मामले का पता चला है।

- वित्तीय समावेशन की समस्या ग्रामों में बैंकिंग शाखाओं की कमी
- PM जनधन योजना के अंतर्गत खोले गये खातों में लेनदेनों का प्रयोग न किया जाना।

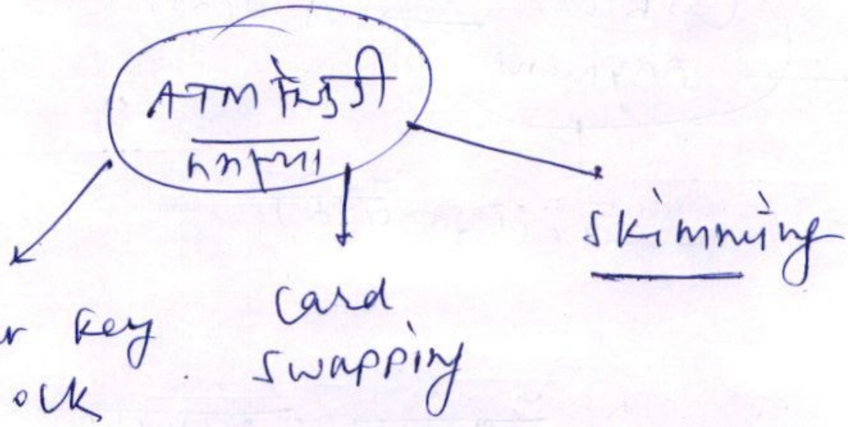

- वित्तीय तंत्र के संबंध में ग्राहकों में जागरूकता का अभाव।
- बैंकों में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की अनुपलब्धता.

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान :

- बैंको द्वारा ग्राहकों को समय समय पर उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करना।
- बैंको द्वारा प्रभावी डाटा सुरक्षातंत्र का विकास करना।
- RBI द्वारा बैंकिंग प्रतिस्पर्धा का ध्यान रखते हुए अधिक लघुबैंको व पेमेंट बैंकों को लाइसेंस जारी करना।
- बैंको में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की नियुक्ति।
- भारतीय बैंकों द्वारा बाहरी बैंको के साथ मिलकर उपयुक्त डाटा सुरक्षा विनियमनों का विकास करना।

8. Abysmal level of formally skilled workers in Indian economy, as indicated by the Labour Bureau Report 2014, is a cause of concern. What are the factors responsible for such a scenario? Also, examine the measures taken by the government in recent years to address the relevant concerns.

श्रम ब्यूरो रिपोर्ट 2014 द्वारा यथा इंगित, भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों का अति निम्न (Abysmal) स्तर, चिंता का कारण है। ऐसे परिदृश्य के लिए उत्तरदायी कारक कौन-से हैं? साथ ही, प्रासंगिक चिंताओं को दूर करने हेतु हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए।

श्रम ब्यूरो रिपोर्ट के सर्वे अनुसार भारत की 90% से अधिक व्यक्ति अकुशल है जबकि दक्षिण कोरिया में 96%, जापान में लगभग 80% व्यक्ति कुशल हैं

उत्तरदायी कारण :

- भारत में कौशल विकास हेतु उपयुक्त संस्थागत ढांचा का अभाव
- भारत में मांग आधारित कौशल का ध्यान देने के बजाय आपूर्ति आधारित कौशल बांटना, मांग के अनुरूप कौशल न देना
- कौशल संस्थानों का अभाव
- भविष्य के अनुरूप अनुकूल प्रौद्योगिकी के बजाय वर्तमान तकनीकी में कौशल देना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जबकि वर्तमान तकनीक कुछ समय पश्चात समाप्त हो जायेगी।

- उपयुक्त प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव।

सरकार द्वारा उठाये गये कार्य:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा 2022 तक 50 करोड़ व्यक्तियों का कौशल विकास किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त उत्तरप्रदेश व बिहार में कौशल बैंकों की स्थापना की जायेगी। जिसके द्वारा मांग आधारित कौशल प्रदान किया जायेगा।
- प्रादेशिक आधार पर कौशल विकास किया जायेगा। उस क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं को देखते हुए कौशल विकास हेतु गतिविधियां प्रारंभ की जायेंगी।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समीक्षा :

- भारत द्वारा किये गये कार्यक्रमों की निगरानी हेतु उपयुक्त निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- कौशल विकास आधुनिक प्रौद्योगिकी- रोबोटिक्स, नैनो तकनीकी को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
- वैश्विक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास की आवश्यकता है जैसे- जापान में वृद्ध आबादी के बढ़ने से हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में रोजगार की संभावना के परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास होना आवश्यक है।

जनसांख्यिकी लाभांश → कौशल विकास → रोजगार → अर्थव्यवस्था सुधार

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. In the 10 years of its existence MGNREGA has won laurels as well as attracted criticism. Comment. What changes are required for the scheme to be relevant in the current scenario.

अपने अस्तित्व के 10 वर्षों में मनरेगा ने ख्याति अर्जन के साथ ही आलोचनाएं भी झेली है। टिप्पणी कीजिए। वर्तमान परिदृश्य में योजना को प्रासंगिक बनाने के लिए कौन से परिवर्तनों की आवश्यकता है?

मनरेगा कार्यक्रम 2005 में योजना के रूप से प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण वयस्क सदस्यों अकुशल रोजगार (न्यूनतम 100 दिन) प्रदान करना था।

- मनरेगा के द्वारा ग्रामीण प्रवसन में कमी आयी
- पलायन मांग में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा
- 100 दिन निश्चित रोजगार के साथ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया
- महिलाओं की प्रभावी भागीदारी (50% से ज्यादा) से आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं की पकड़ मजबूत हुई। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हुआ

- मनरेगा के अंतर्गत जलविज्ञान कृषि संबंधी तथा कृषिगत कार्य हुए।

आलोचना -

- मनरेगा द्वारा 100 दिन निश्चित कार्य देने से कृषि हेतु मजदूरों की लागत में वृद्धि होने से किसानों को नुकसान हुआ।
- ग्रामीण आय बढ़ने से मुद्रास्फीति की समस्या
- मनरेगा द्वारा परिसंपत्ति निर्माण न किया जाना। फर्जी दस्तावेजों द्वारा लीकेज की समस्या।
- मनरेगा के अंतर्गत कई गांवों में ऐसे मामले सामने आये जहां सरपंच द्वारा विनाश किये हुए कुआ धन अपने पास रखा अन्य धन को श्रमिकों में बंटवारा किया गया।

परिवर्तनों की आवश्यकता :

- मनरेगा की आधार कार्ड के साथ सिबद्धता द्वारा प्रभावी बनाने की आवश्यकता।
- उपयुक्त नागरिक केन्द्रों की व्यवस्था करना
- प्रबंधन सूचना तंत्र को प्रभावपूर्ण व संस्थागत ढंग से लागू करना
- दुर्भागता क्षेत्रों में मनरेगा दिवसों की वृद्धि करना
- मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान देना तथा जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उपशमन व अनुकूलन गतिविधियों पर बल देना।
- ग्राम सभा को मनरेगा की उपयुक्त निगरानी हेतु संस्थागत रूप से संसाधन उपलब्ध कराना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Power sector reforms, crucial as they are, have remained elusive. Discuss the reasons for their failure. How far can the UDAY scheme address the issues concerning DISCOMS and improve the entire power sector value chain?

बिजली क्षेत्र में सुधार अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के बावजूद दुष्प्राप्य बने हुए हैं। इनकी विफलता के कारणों पर चर्चा कीजिए। उदय (UDAY) योजना डिस्कॉम (DISCOMS) से संबंधित समस्याओं को किस सीमा तक समाधान कर सकती है और समस्त विद्युत क्षेत्रक मूल्य श्रृंखला(power sector value chain) में कैसे सुधार ला सकती है?

बिजली क्षेत्र के कई समस्याओं के कारण यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में प्रभावी योगदान नहीं दे रहा है।

~~समस्याएं~~/ विफलता के कारण :

- राज्य बिजली बोर्डों के पास संसाधनों का अभाव
- बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का नुकसान में लगातार बने रहना।
- बिजली टैरिफों के युक्तिसंगत न होने के कारण बिजली कंपनियों का लगातार नुकसान
- पारेषण व वितरण नुकसान (AT&C loss)
- विभिन्न समितियों - शुंगलू कमेटी की रिपोर्टों को प्रभावी ढंग से लागू न करना।

उदय योजना द्वारा डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) के नुकसान को राज्यों द्वारा अधिग्रहित किया जायेगा और भविष्य में राज्यों द्वारा उनके नुकसान की भरपाई मॉनिटर प्रदान किया जायेगा।

डिस्कॉम के नुकसान की समस्या।

वर्तमान में डिस्कॉम वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण बिजली नहीं खरीद रही है जिसके कारण उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

(बिजली निर्माण कंपनी) → (DISCOM) → (उपभोक्ता)

विद्युत क्षेत्र शृंखला

- DISCOM के नुकसान से इसकी मूल्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

- उदय योजना विद्युत क्षेत्र में प्रभावी सुधार। उपभोक्ता व निगमों की समस्याओं का समाधान करेगी।
- निगमों द्वारा बिजली खरीद से उपभोक्ता को प्रभावी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- सरकारी बोर्ड मार्केटर बिना घाटा होगा।

11. Market volatility and vulnerability to weather are the major issues facing Indian agriculture. Elaborate. In this regard, critically examine the importance of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana vis-a-vis earlier insurance schemes in addressing the problems of Indian agriculture.

बाजार की अस्थिरता और मौसम के प्रति सुभेद्यता (vulnerability to weather) भारतीय कृषि के समक्ष बड़ी समस्याएं हैं। वर्णन कीजिए। इस संबंध में भारतीय कृषि की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में पूर्व की बीमा योजनाओं की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या परिवर्तनशील. वैश्विक बाजार के कीमतों में उतार चढ़ाव तथा परिवर्तनशील मौसमी परिस्थिति है

कृषि

बाजारी अस्थिरता
↓
- वैश्विक बाजार में मांग में परिवर्तन
- ज्यादा मांग
- भारतीय बाजार की वैश्विक बाजार से संबद्धता का प्रभाव

मौसम परिवर्तन
↓
जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन के कारण कृषि पर विपरीत प्रभाव
↓
- उष्ण लहर की आवृत्ति में अधिकता
- लगातार 2 वर्षों तक सूखे की समस्या

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभाव :

- अन्य योजनाओं की तुलना में इसके अंतर्गत रबी व खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम निर्धारित किया गया है। किसानों की हानि की स्थिति में पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी।
- फसल नुकसान हेतु खेत को इकाई के रूप में माना गया है।
- प्राकृतिक आपदाओं द्वारा नुकसान के साथ फसलोत्तर (फसल कटाई पश्चात) नुकसान पर भी ध्यान दिया गया है।
- खेतों की उपयुक्त निगरानी व हानि की जांच हेतु तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया गया है। किसानों द्वारा खेत की तस्वीर भेजकर हानि का क्लेम किया जा सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- बीमा कंपनियों को उत्तरदायी बनाते हुए उपयुक्त नियामगत तंत्र विकसित किया गया है
- किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति भरपाई हेतु प्रक्रियाओं सरल व त्वरित बनाया गया है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. The Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) is a step forward from the New Exploration Licensing Policy (NELP). Compare the two policies and elaborate how HELP can encourage investment in the hydrocarbon sector as well as curtail India's export dependence?

हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन (अन्वेषण) लाइसेंसिंग पॉलिसी (नीति) [HELP], न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) से एक कदम आगे है। दोनों नीतियों की तुलना कीजिए और वर्णन कीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में HELP किस प्रकार सहायता प्रदान सकता है?

HELP नीति में प्रभावी विशोधन का इसे व्यापक बनाते हुए HELP नीति प्रस्तुत की गई है।

- HELP में तेल, गैस, शैल के लिये अलग अलग लाइसेंस के स्थान पर ही ब्लॉक के लिये एक ही लाइसेंस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
- Production sharing model को अपनाया गया है।
- नीलामी की उपयुक्त व्यवस्था।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- HELP नीति में निवेश को प्रोत्साहित हेतु एकल लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई है। इससे ब्लाक आवंटन प्रक्रिया को बल मिलेगा।
- भारत में शैल गैस, हाइड्रोकार्बन खोज होने के साथ आयातक निर्भरता घटेगी क्योंकि HELP व्यवस्था से निजी निवेशक आकर्षित होंगे तथा अन्वेषण प्रक्रियाओं बल मिलेगा।
- निजी कंपनियों द्वारा पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। निजी कंपनियों द्वारा प्रभावी अन्वेषण हाइड्रोकार्बन विकास/खोज में सहायता करेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Although equal land ownership rights are essential for the economic empowerment of women, these rights are often overlooked. Discuss. What steps have been taken by the government to ensure land rights for women?

यद्यपि समान भूमि स्वामित्व अधिकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं परन्तु इन अधिकारों की प्रायः अनदेखी की जाती रही है। चर्चा कीजिए। महिलाओं के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

समान भूमि स्वामित्व अधिकार महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है। महिलाओं को भूमि स्वामित्व अधिकार होने से उनकी आर्थिक निर्णयात्मक पहुंच सुनिश्चित होगी।

भूमि स्वामित्व अधिकार

↓

आर्थिक स्वाधीनता

↓

सामाजिक मानकों - शिक्षा, बचत या कर्ज

↓

महिला सशक्तिकरण

परंतु ग्रामीण तथा पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को स्थायी अधिकार नहीं दिये जाते हैं।

सरकार द्वारा किये गये प्रयास :

- सरकार द्वारा और स्थानीय महिलाओं के नामपर हस्तांतरण की दिशा में कदम उठाये गये हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में राशनकार्ड महिला मुखिया के नामपर बनाये जाने का प्रावधान है।
- उत्तराखण्ड कानून ने 2008 में प्रयास कर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिये गये हैं।
- महिलाओं के नामपर भूमि पट्टे को देने का प्रावधान।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Micro irrigation methods would not only lead to increased productivity but also conservation of water. Enumerating the different methods of micro irrigation, identify the bottlenecks in their implementation and benefits that can acrue once they are implemented.

सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों से न केवल उत्पादकता ब्रढ़ेगी बल्कि जल संरक्षण भी होगा। सूक्ष्म सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों को गिनाते हुए उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं एवं उनके कार्यान्वयन से प्राप्त हो सकने वाले लाभों की पहचान कीजिए।

सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों द्वारा उत्पादकता में वृद्धि व जल संरक्षण सुनिश्चित होगा।

सूक्ष्म सिंचाई पद्धति :

- ड्रिप सिंचाई
- स्प्रिंकलर सिंचाई

कार्यान्वयन में बाधा :

- ज्यादा लागत अधिक होने के कारण किसानों द्वारा न अपनाना।
- सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए Priority sector lending के तहत कर्ज न देने का प्रावधान, जिससे इन पद्धतियों को अपनाने हेतु वित्त का अभाव

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- किसानों के बीच इन पद्धतियों के प्रति कम जागरूकता।
- इन पद्धतियों को अपनाने हेतु उपयुक्त तकनीकी का अभाव

लाभ :

- इस सिंचाई पद्धति से जल संरक्षण के साथ बाढ़ पद्धति (flood technique) द्वारा होने वाली जल की बर्बादी रुकेगी।
- सतही सिंचाई द्वारा होने वाली क्षारीयता, जलप्लावन (water logging) की स्थिति से निजात मिलेगी।
- फसलों हेतु अनुकूलतम जल देने से उनकी पोषण क्षमता में वृद्धि होगी तथा उत्पादकता में वृद्धि होगा।
- उर्वरकों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित होगा। अन्यथा बिना इस सिंचाई के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आवश्यकता समानव उर्वरकों की मात्रा के साथ बचत हो जाती है।

- उर्वरकों के व्यर्थ जल के साथ न बहने से यूट्रोफिकेशन की समस्या से मुक्ति मिलेगी।
- जल का अनुकूलतम प्रयोग से फसलों द्वारा उर्वरकों का प्रभावी अवशोषण होगा जिससे मृदा की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. It has been argued that the Nutrient based subsidy (NBS) scheme launched in 2010 has created more problems than it intended to solve. Examine. What measures are required to address concerns arising out of the fertilizer subsidy policy in India?

ऐसी दलीलें दी जाती रही हैं कि वर्ष 2010 में आरंभ की गई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एन.बी.एस.) योजना ने समस्याओं के समाधान के बजाए कहीं अधिक समस्यायें उत्पन्न की हैं। परीक्षण कीजिए। भारत में उर्वरक सब्सिडी नीति से उत्पन्न चिन्ताओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है?

पोषण आधारित सब्सिडी के अंतर्गत पोषक तत्वों के आधार पर (N, P, K) सब्सिडी दी जाती है। यद्यपि इस योजना की कई आधारों पर आलोचना की जाती है।

- NBS के अंतर्गत यूरिया को सम्मिलित नहीं किया गया। जबकि वर्तमान में सर्वाधिक सब्सिडी यूरिया पर दी जाती है।
- यूरिया पर सब्सिडी देने के कारण N:P:K में असंतुलन की स्थिति से मृदा उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- यूरिया को NBS प्रणाली से बाहर रखने के कारण यूरिया फर्मों की दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि यूरिया पर सब्सिडी पोषकतत्वों की मात्रा के बजाय

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उत्पादन लागत के आधार पर दी जाती है। जिससे अकुशल व अदक्ष फर्मों को आयके सरकारी लाभ होती है।

उर्वरक नीति से संबंधित उपाय :
वर्तमान में सरकार द्वारा कई उपाय किये गये
नीम कोटेड यूरिया के द्वारा यूरिया का केवल कृषि कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा किसानों को मृदा में निवेश की जानकारी देना।

संभावित अन्य उपाय :
वर्तमान में Cannelization की समस्या है। आयात स्रोत हेतु मात्र 3 फर्मों को अनुमति दी गई है तथा उनकी कुल आयात की मात्रा, इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- खाद्यों को NBS प्रणाली के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है।
- शोरा के सस्ते होने के कारण विदेशों (बांग्लादेश, नेपाल) में इनका निर्यात किया जाता है। इसे रोकने हेतु उपयुक्त निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- शांता कुमार कमेटी के निर्देशों के अनुरूप उर्वरकों पर सब्सिडी को किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है जिससे लीकेज की समस्या कम हो।
- उर्वरक कंपनियों के 'Exit' नीति से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी उपाय करना।

16. The success of "Operation Flood" proves that thoughtful intervention in the livestock sector has the potential of acting as a growth engine for the agriculture sector and rural economy. In light of this, examine the potential of the livestock sector and the challenges it faces. Also enumerate the steps taken by the government in recent years to leverage the potential of this sector.

"ऑपरेशन फ्लड" की सफलता से सिद्ध होता है कि पशुधन क्षेत्रक (लाइवस्टॉक सेक्टर) के लिए उठाए जाने वाले विचारशील कदमों में कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु विकास इंजन के रूप में कार्य करने की क्षमता है। इस तथ्य के आलोक में, पशुधन क्षेत्रक की क्षमताओं एवं उसके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही, सरकार द्वारा हाल के वर्षों में इस क्षेत्रक की क्षमता का लाभ प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदमों को गिनाइए।

पशु क्षेत्र कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक विकास इंजन है पशुधन प्राकृतिक आपदा व फसल फेलने के समय प्राकृतिक बीमा के रूप में कार्य करते हैं

पशुधन पर स्वामित्व फसल स्वामित्व की तुलना में अधिक समावेशी (भूमि स्वामित्व की तुलना में) है 70% पशुधन पर स्वामित्व 67% लघु व सीमांत कृषकों का है

पशुधन के साथ और, इसके रूप में किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है तथा फसल फेलने के समय उन पर कम विपरीत प्रभाव पड़ता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- पशुपालन द्वारा क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। उन क्षेत्रों में सूखे का असर कम दृष्टिगत होता है जहां किसानों के पास पशुधन के रूप में अतिरिक्त आय का स्रोत होता है।

पशुधन द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रोटीन:

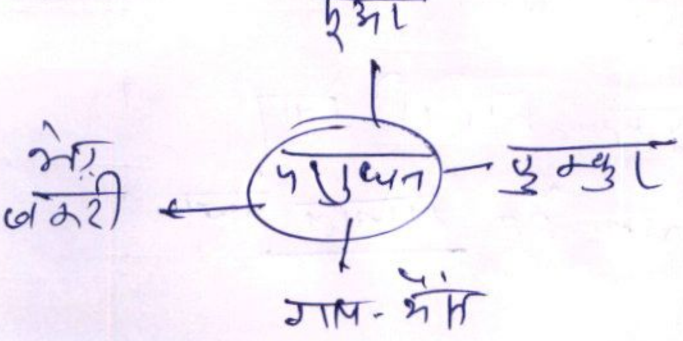

मुर्गा/मुर्गी:
- मक्के की कम उपलब्धता
- एविअन (बर्ड फ्लू) का खतरा

गाय-भैंस -
- पशुओं हेतु चारे की कम उपलब्धता

फसल क्षेत्र के बढ़ने के कारण चारागाह संकुचित होती जा रही है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- पशुओं के बीमारी समाधान हेतु पशु चिकित्सालयों की कमी
- पशु टीकाकरण अभाव
- पशु विश्वविद्यालयों की कम संख्या जिसके कारण पशु उत्पादों की उपयुक्त जानकारी नहीं।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम :

- पशुपालकों को उपयुक्त जानकारी देना
- देशी नस्लों के विकास हेतु गोपाल योजना प्रारंभ करना।
- राष्ट्रीय डेयरी मिशन की स्थापना

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. What are the twin objectives of government food procurement policy in India? Discuss the instruments of this policy. Do you think there is an urgent need for rationalization of MSP policy in India?

भारत में सरकारी खाद्य खरीद (अधिप्राप्ति) नीति के दोहरे उद्देश्य क्या हैं? इस नीति के साधनों पर चर्चा कीजिए। क्या आप यह मानते हैं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) नीति को तत्काल युक्तिसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है?

भारत में सरकारी खाद्य खरीद एक प्रमुख नीतिगत कार्य है इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं

- गरीबों / कमजोर वर्गों को कम दरों पर खाद्य उपलब्ध कराना
- किसानों को बाजार संकट के समय उनकी फसल खरीद हेतु MSP के रूप में एक उपयुक्त न्यूनतम तंत्र उपलब्ध कराना

=> गरीबों / कम आय वर्गों को कम दरों पर खाद्य उपलब्ध कराने का कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक खाद्य वितरण (PDS) प्रणाली द्वारा किया जाता है इसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना भी शामिल है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के अंतर्गत कामान्यतया 24 फसलों की खरीद हेतु संस्थागत तंत्र उपलब्ध है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में MSP नीति को प्रभावित बनाने की आवश्यकता है।

MSP के कमियाँ:

- वर्तमान में MSP नीति के गेहूं-चावल के पक्ष में होने के कारण दलहन फसलों को नुकसान उठाना पड़ता है। MSP नीति में सामाजिक व पर्यावरणीय लाभ को भी समाहित करने की आवश्यकता है।
- MSP के उत्तर-पश्चिमी पंजाब, हरियाणा राज्यों में अधिक प्रभावी होने के कारण पूर्वी राज्यों (बिहार, उड़ीसा, झारखंड) तथा पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- MSP के संबंध में किसानों में जागरूकता का अभाव।
- MSP के अंतर्गत खरीदारी भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है इस निगम के कार्यों पर उपयुक्त संस्थागत निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- MSP को दलहन फसलों के लिए लाने के खाद्यान्नों से हटा उर्वरकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- MSP के अंतर्गत खरीदारी बड़े किसानों से की जाती है इस नीति का लाभ लघु व सीमांत कृषकों को नहीं मिलता है क्योंकि इनके द्वारा उत्पादन केवल स्वयं के उपभोग के लिए ही होता है। जबकि MSP का बढ़ना से खाद्य मुद्रास्फीति का लघु, सीमांत किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार MSP को तत्काल उचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Discuss the potential of Food Processing Industry with regards to employment generation in India. What are the key impediments which need to be overcome before the sector can become internationally competitive and achieve high growth?

भारत में रोजगार सृजन करने के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। वे प्रमुख बाधाएँ कौन-सी हैं जिन्हें इस क्षेत्रक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उच्च विकास प्राप्त करने हेतु दूर किए जाने की आवश्यकता है?

भारत में कृषि क्षेत्र को प्रभावी बनाने हेतु तथा रोजगार वृद्धि हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

- फास्ट फूड व वैश्विक बाजार में खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण का वर्तमान में निचला स्तर है जिसे बढ़ाने हेतु रोजगार की आवश्यकता।
- महिला कामकाजी के बढ़ने से 'Ready to cook food' की बढ़ती मांग, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उपयोगिता की संभावना बढ़ती है।
- कोल्ड स्टोरेज, भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण खाद्य का काफी नुकसान होता है जिसे कम करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित होने से रोजगार बढ़ेगा जिससे ग्रामीण प्रवसन की मात्रा भी कम होगी।

- प्रमुख बाधाएं - निम्न बाधाओं के होते से यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा -

1) भण्डारण समस्या - कोल्ड स्टोरेज, भंडारण का अभाव। वर्तमान में 80% से अधिक स्टोरेज सरकारी है। तथा इनमें से 70% से अधिक का प्रयोग आलू प्याज के भंडारण में किया जाता है।

- ला.क. लिंक नेटवर्क का अभाव

2) खाद्य प्रसंस्करण नीति का अभाव - खाद्य राष्ट्रीय ढांचा हेतु उपयुक्त विनियमनों का अभाव तथा उनके बीच राज्यगत विभिन्नता।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वित्त उपलब्धता की समस्या

4) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपयुक्त अनुसंधान विकास (R&D) का अभाव

- स्वदेशी तकनीक का प्रभावी न होना।
- सरकारी / निविदाओं का प्रभावी उपयोग न हो पाने के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

5)

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Mixed farming for the resource poor farmer is mostly a poverty induced option. Comment. What role can the government play to help farmers realise the potential from mixed farming.

संसाधनहीन निर्धन किसानों के लिए मिश्रित कृषि मुख्य रूप से निर्धनता प्रेरित विकल्प है। टिप्पणी कीजिए। मिश्रित कृषि की संभावनाओं को साकार करने हेतु, सरकार किसानों का सहयोग करने में क्या भूमिका निभा सकती है ?

मिश्रित कृषि से आशय फसल व पशुपालन से है निर्धन किसानों के पास उपयुक्त संसाधनों के अभाव के कारण इनके द्वारा फसलों का उत्पादन व पशुपालन साथ-साथ किया जाता है

- निर्धन किसानों द्वारा फसलों हेतु उर्वरक आपूर्ति पशु अपशिष्ट गोबर आदि के द्वारा की जाती है
- पशु-फसल आपदा के समय प्राकृतिक बीमा के रूप में भी कार्य करते है जिससे किसानों को सूखे के समय कम हानि का सामना करना पड़ता है
- गरीब किसानों द्वारा मिश्रित कृषि निर्धनता से होती है क्योंकि इनके पास फसल उत्पादन हेतु उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशकों की खरीद हेतु

उनके पास वित्त का अभाव है।

- पशुओं के माध्यम से निर्धन किसानों की आय बढ़ेगी - दूध, अंडा आवश्यकताएँ भी पूरी होंगी।

निष्कर्ष : वास्तविक निर्धनता को गरीब किसानों द्वारा नहीं पहचाना जाता है। इस संबंध में निम्न एक उपयुक्त रणनीति लिया सकती है।

- गरीब किसानों में शिक्षित मामला हुआ गरीब किसानों में किशोर कृषि के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- किसानों को जानकारी देना फसलों के उत्पादन को बढ़ाना। किसानों को वित्त उपलब्ध करवाना पशुधन विकास करना।
- किसानों को आधुनिक पशुपालन गतिविधियों के संबंध में जानकारी देना।
- पशुओं के इलाज / चिकित्सा हेतु पशु

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

शीतिकालयों की मांग में निवारण करना तथा गरीब किसानों की इन शीतिकालयों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना।

गरीब किसानों को पशु उत्पाद बेचने हेतु उपयुक्त विपणन तंत्र उपलब्ध कराना।

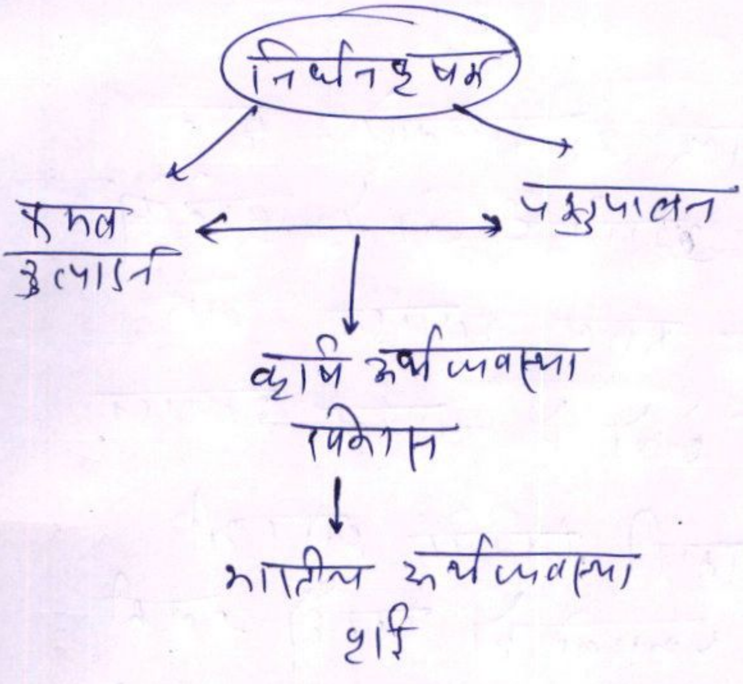

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. What do you understand by cropping pattern? What are the factors that influence the cropping pattern in India? Is there a need to change the cropping pattern in the country keeping the agro-ecological concerns in mind?

फसल प्रतिरूप (क्रॉपिंग पैटर्न) से आप क्या समझते हैं? भारत में फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कृषि-पारिस्थितिकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए क्या देश में फसल प्रतिरूप को परिवर्तित करने की आवश्यकता है?

फसल प्रतिरूप से तात्पर्य किसी स्थान विशेष में बोये गये फसल से है। भारत में फसल प्रतिरूप कई कारकों से प्रभावित होता है-

- कृषकों की भोजन आवश्यकताएं- कृषक सामान्यत: वही उगाते हैं जो वे खाते हैं
- मृदा के अनुरूप फसल उत्पादन - जैसे तराई व डेल्टाई क्षेत्रों में चावल उत्पादन.
- वर्तमान में सरकारी नीतियों द्वारा भी फसल प्रतिरूप प्रभावित हो रहा है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी जलगहन फसलों (चावल; गन्ना) बोया जा रहा है क्योंकि इनकी खरीद हेतु MSP तंत्र उपलब्ध है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी फसल प्रतिरूप निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए बड़े किसानों द्वारा व्यापारिक बाजार हेतु फसलों का उत्पादन किया जाता है जबकि लघु व सीमांत कृषक उपभोग हेतु उत्पादन करते हैं।

- सिंचाई की आवश्यकता के अनुरूप - सिंचाई साधनों की उपलब्धता फसल प्रतिरूप को प्रभावित करती है। वर्षाधीन क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध न होने के कारण मोटे अनाज बोये जाते हैं।

- सरकार द्वारा तकनीकी की पहुंच कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। उसके अनुरूप फसल प्रतिरूप निर्धारित होता है।

- जलवायु / प्राकृतिक स्थितियों के अनुरूप - जिनमें तापमान, वर्षा प्रमुख है। जिनके द्वारा फसल प्रतिरूप निर्धारित होता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

=) वर्तमान में देश में फसल प्रतिरूप को कृषि-जलवायविक परिस्थितियों के अनुरूप अपनाना चाहिए।

. महाराष्ट्र, विदर्भ जैसे जल विहीन क्षेत्रों में जलगहन- गन्ना, कपास फसलों की खेती नहीं करनी चाहिए।

. सरकारी MSP प्रणाली को दलहन के पक्ष में झुकाने की आवश्यकता है।

. फसल प्रतिरूप का निर्धारण मानसूनी जलवायु व सिंचाई व्यवस्थाओं देखते हुए करना चाहिए।